भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4429
दिनांक 27 मार्च, 2025

अन्वेषण कार्यकलापों की गति

†4429. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अन्वेषण कार्यकलापों की गति में तेजी लाने के लिए कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र का ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने में क्या महत्व है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) और अन्य प्रचालकों को क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के नए संभावित स्रोतों की खोज करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत और प्रौद्योगिकीय पहल की हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण हेतु नीति, 2014

ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015

iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016

iv. पीएससीज के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017

v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017

vi. राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी की स्थापना, 2017

vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिनों में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

viii. तेल और गैस के लिए उन्नत पुनर्प्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018

ix. मौजूदा उत्पादन साझाकरण सुंविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति ढांचा, 2018

x. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020

xi. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के अंतर्गत कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) को सुविधाजनक बनाने के लिए और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2019, ओएएलपी ब्लॉकों में कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।

xii. वर्ष 2022 में दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध अपतटीय क्षेत्र के लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को खोल दिया जाएगा।

xiii. सरकार भारतीय तलछटी बेसिनों के गुणवत्तापूर्ण डेटा को बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए भूमि और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे भूमि पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

xiv. प्रसंस्करण और व्याख्या के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्राप्त करने के लिए एयरबोर्न ग्रेविटी ग्रैडिओमेट्री और ग्रेविटी मैग्नेटिक सर्वे, पैसिव सिस्मिक टोमोग्राफी (पीएसटी), लो-फ्रीक्वेंसी पैसिव सिस्मिक (एलएफपीएस) सर्वेक्षण जैसी नई प्रौद्योगिकियों को लागू किया गया है।

अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) गतिविधियाँ विभिन्न कार्य तंत्रों के माध्यम से आयातित तेल और गैस पर देश की निर्भरता को कम करने में योगदान देती हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान क्रूड ऑयल का उत्पादन 29.36 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) रहा है और वर्तमान में ईएंडपी कंपनियों द्वारा लगभग 53% गैस (36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर) घरेलू स्तर पर उत्पादित की जा रही है।

****